12.12 hrs.

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

JOINT COMMITTEE ON MARRIAGE LAW (AMENDMENT) BILL

SHRI R. MALLANNA (Chitradurga): I beg to move:

"That this House do further extend upto the last day of the Winter Session, 1982, the time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954."

MR. SPEAKER: Shri R. L. P. Verma.

आप करना चाहते हैं ?

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं क्योंकि ला कमीशन ने भी प्रोसेस किया है।....

MR. SPEAKER: बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप कहिये कि मूव कर रहे हैं।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : मेरे कहने का अर्थ यही है कि इतना समय न बढ़ाया जाय। करेंट सेशन तक ही रखा जाय। या बहुत अधिक अगर बढ़ाया ही हो तो मोनसून सेशन न रख दें।

I beg to move:

"That in the motion,

for the words "Winter Session, 1982"

substitute "current session".

MR. SPEAKER: Mr. Harikesh Bahadur.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): I shall move it. Kindly allow me to speak. The extension should not be given. This is a very important Bill. We want at least that this should come up in the current session itself.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): It is not possible.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Why is it not possible?

MR. SPEAKER: That is all right.

I shall now put the amendment moved by Shri R. L. P. Verma.

The Amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do further extend upto the last day of the Winter Session, 1982, the time for presentation of the Repor tof the Joint Committee on the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954."

The motion was adopted.

12.13 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. SPEAKER: Now, matters under 377. Shri Negi.

[MR. DEPUTY-SPEAKER—*in the Chair*]

(i) MEASURES FOR ECONOMIC PROGRESS AND DEVELOPMENT OF TRIBAL AREAS OF DEHRADUN DISTRICT, U.P.

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले का जौनसार बावर क्षेत्र जिसमें कालसी एवं चकरौता विकास क्षेत्र सम्मि-

[श्री टी० एस० नेगी]

लित हैं, को सरकार ने जनजाति क्षेत्र बहुत वर्षों पहले घोषित किया था । वहां की जनता को वैसे काफी लाभ भी हुआ, क्षेत्र की तरक्की हुयी इसी प्रकार से टेहरी गढ़वाल जिले का जौ पुर क्षेत्र एवं उत्तरकाशी जिले का रवाई क्षेत्र जिसमें पुरौला नौगांव एवं मोरी ब्लाक सम्मिलित हैं, को भी जन-जाति क्षेत्र घोषित किया जाय । इसमें उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। इस जन-जाति क्षेत्र का मुख्यालय क्षेत्र के मध्य में होना चाहिये था जिससे लोगों को सम्पर्क की सुविधा हो ।

रवाई जौनपुर क्षेत्र प्रदेश में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । सामन्ती व्यवस्था में भी इस क्षेत्र की उपेक्षा ही होती रही । फलस्वरूप सन् 1930 में रवाई कान्ड हुआ जिसमें सैकड़ों व्यक्ति शहीद हुये, तानाशाही की गोली के शिकार हुये । आज भी वहां के लोगों को जन-जाति क्षेत्र की पूरी सुविधा न मिलने के कारण एवं उनकी जायज मागों की अवहेलना होने की वजह से वहां आन्दोलन का वातावरण बन चुका है । वहाँ के नौजवान अपनी मांगों के लिए हर जायज तरीके से आन्दोलन करेंगे और जब तक उनकी सुनवायी न हो जाये और उनकी जायज मांगें पूरी न हो जायें यानी जौनपुर एव रवाई को उसी के साथ लगे हुए जौनसार एवं बावर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती (जो एक ही जन जाति क्षेत्र के अंग हैं) तब तक वहां की जनता संघर्ष रत रहेगी । इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जन-जातियों में असंतोष का वातावरण पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है । क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जन-जातियों के उत्थान और विकास का काम नहीं हो रहा है । इन जन-जातियों के उत्थान की जिम्मेदारी न केवल राज्य सरकार की है, बल्कि केन्द्र सरकार की भी है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ खींचते हुए प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में प्रभावशाली कदम शीघ्रता से से उठाये जायें ।

(ii) EVASION OF DUTY ON STAINLESS STEEL

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): The stainless steel re-rollers in the country are very much perturbed over the recent phenomenon of large quantities of stainless steel sheets being dumped in the country by dubious means. Besides putting the indigenous industry out of gear these imports have been depriving the Government of its legitimate revenue in form of import duty.

It is stated that large quantities of cold rolled stainless sheets totalling over 2,500 tonnes have already been brought in the country in the form of folded angles and in the process the Government lost about Rs. 11 crores. If no action is taken to remove the loophole in the import policy, which makes this business possible, another shipment of 7,000 tonnes is expected to arrive and dump the goods in Indian shores, putting the Government to a further loss of Rs. 30 crores.

The modus operandi of the whole scheme is like this: According to the import policy for the year 1980-82, the stainless steel sheets are canalised for imports through the MMTC and the customs duty payable on these sheets is 220 per cent plus 30 per cent auxiliary and Rs. 363 per tonne CVD. These sheets, however, can be brought here under OGL if they are imported by "actual users" in the form of folded angles and circles with the current customs duty of 60 per cent plus 25 per cent auxiliary plus Rs. 363 per tonne CVD. Prior to the budget of 1982-83, the duty was only 35 per cent plus 10 per cent Rs. 363 per